

राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समिति शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराकर वर्गों के पछिड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिये विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएँ लागू की जाएंगी। इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- सर्वेक्षण कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में संपादित किया जाएगा। साथ ही, सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर नगिम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएँ ले सकेंगे।
- इस कार्य के लिये नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएँ एवं आँकड़े ऑनलाइन फीड किये जाएंगे। इसके लिये सूचना-प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पृथक् से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गई सूचनाएँ विभाग सुरक्षित रखेगा।